भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2024 के

तारांकित प्रश्न सं. 31 का उत्तर

रेलवे की लंबित परियोजनाएं

***31. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**
श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र और बिहार में लंबित रेल परियोजनाओं और विशेष रूप से समस्तीपुर, खगड़िया, मुंबई उत्तर पश्चिम, ठाणे और कल्याण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो लंबित और/या विचाराधीन परियोजनाओं के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित परियोजनाओं, यदि कोई हों, को पूरा करने की समय-सीमा क्या है; और

(घ) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बजटीय प्रावधानों, इस अवधि के दौरान वास्तविक व्यय और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बजटीय प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

रेलवे की लंबित परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और श्री नरेश गणपत म्हस्के के तारांकित प्रश्न सं. 31 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति राज्य-वार या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेलवे-वार किया जाता है क्योंकि भारतीय रेल परियोजनाएं राज्य की सीमाओं/संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

रेल परियोजनाओं को स्वीकृति देना भारतीय रेल की एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। रेल अवसंरचना परियोजनाएं लाभप्रदता, अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता, अनुपलब्ध कड़ियां और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों के विस्तार, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर शुरू की जाती हैं, जो चालू परियोजनाओं की दायितायों, धन की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करती हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र और बिहार सहित भारतीय रेल में 488 परियोजनाएं (187 नई लाइनें, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण), जिनकी कुल लंबाई 44,888 किलोमीटर तथा लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रु. है, जो योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। इसका सार निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइन	187	20,199	2,855	1,60,022
आमान परिवर्तन	40	4,719	2,972	18,706
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	261	19,570	6,218	1,13,742
कुल	488	44,488	12,045	2,92,470

<u>महाराष्ट्र</u>

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे और पश्चिम रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। निधि के आबंटन और व्यय सहित रेल परियोजनाओं का परियोजना-वार और क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाले 7,458 किलोमीटर कुल लंबाई के 91 सर्वेक्षणों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण/मल्टी ट्रैकिंग) को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 41 परियोजनाएं (16 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 23 दोहरीकरण) हैं, जिनकी लागत ₹81,580 करोड़ तथा कुल लंबाई 5,877 किलोमीटर है, जो योजना तथा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1,926 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2024 तक ₹31,236 करोड़ का व्यय किया गया है। इसका सार निम्नानुसार है :-

कोटि	परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)	परिव्यय 2024-25 (करोड़ रु. में)
नई लाइन	16	2017	166	8529	2125
आमान परिवर्तन	2	609	312	3332	800
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	23	3251	1448	19376	4317
कुल	41	5877	1926	31236	7242

महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए औसत बजट आबंटन निम्नानुसार है :-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के औसत आवंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	1171 करोड़ रु. प्रति वर्ष	-
2024-25	15940 करोड़ रु.	13 गुना से अधिक

2009-14 और 2014-2024 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले खंडों (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) की कमीशनिंग का विवरण निम्नानुसार हैः-

अवधि	कमीशन किया गया कुल रेलपथ	रेलपथ की औसत कमीशनिंग	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	292 किलोमीटर	58.4 किलोमीटर प्रतिवर्ष	-
2014-24	1830 किलोमीटर	183 किलोमीटर प्रतिवर्ष	3 गुना से अधिक

मुंबई और निकटवर्ती क्षेत्रों में संकुलन कम करने और यात्रियों की भावी मांगों को पूरा करने के लिए, ₹8,087 करोड़ की लागत पर मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी)-II, ₹10,947 करोड़ की लागत पर एमयूटीपी-III और ₹33,690 करोड़ की लागत पर एमयूटीपी-IIIक को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में मुंबई और निकटवर्ती क्षेत्रों में शुरू की गई परियोजनाओं की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (₹ करोड़ में)
1	सीएसएमटी-कुर्ला पांचवीं एवं छठी लाइन (एमयूटीपी-II) (17.5 कि.मी.)	891
2	मुंबई सेंट्रल-बोरीवली छठी लाइन (एमयूटीपी-II) (30 किलोमीटर)	919
3	हार्बर लाइन गोरेगांव-बोरीवली का विस्तार (एमयूटीपी-IIIक) (7 किलोमीटर)	826
4	बोरीवली-विरार पांचवीं एवं छठी लाइन (एमयूटीपी-IIIक) (26 कि.मी.)	2184
5	विरार-दहाणु रोड की तीसरी एवं चौथी लाइन (एमयूटीपी-III) (64 किलोमीटर)	3587
6	पनवेल-करजत उपनगरीय गलियारा (एमयूटीपी-III) (30 किलोमीटर)	2782
7	एरोली-कलवा (एलीवेटेड) उपनगरीय गलियारा लिंक (एमयूटीपी-III) (4 किलोमीटर)	476
8	कल्याण-आसनगांव के बीच चौथी लाइन (एमयूटीपी-IIIक) (32 किलोमीटर)	1759
9	कल्याण-बदलापुर के बीच तीसरी और चौथी लाइन (एमयूटीपी-IIIक) (14 किलोमीटर)	1510
10	कल्याण-कसारा तीसरी लाइन (67 कि.मी.)	792
11	नायगांव-जूचन्द्रा दोहरी कॉर्ड लाइन (6 कि.मी.)	176
12	निलाजे-कोपर दोहरी कॉर्ड लाइन (5 कि.मी.)	338

इसके अलावा, महाराष्ट्र में फ्लैगशिप हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना पर निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। अब भूमि अधिग्रहण का कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो गया है। पुलों, एक्वेडक्ट आदि के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। समुद्र के नीचे लगभग 21 कि.मी. सुरंग का कार्य करने के लिए 3 टीबीएम के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इसी बीच, शाफ्ट आदि के निर्माण जैसे टीबीएम के कार्य के लिए सभी प्रारंभिक कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं।

वेस्टर्न डीएफसी भी महाराष्ट्र से होकर गुजर रहा है। वेस्टर्न डीएफसी का लगभग 178 मार्ग किलोमीटर महाराष्ट्र में अवस्थित है जो वेस्टर्न डीएफसी की समग्र मार्ग लंबाई का लगभग 12 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में न्यू घोलवड से न्यू वैतरणा तक इस परियोजना का 76 कि.मी. कमीशन कर दिया गया है। शेष कार्य शुरू कर दिए गए हैं। वेस्टर्न डीएफसी से जेएनपीटी तक कनेक्टिविटी होने से पत्तन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक कार्गो और कंटेनर यातायात सम्हालने की क्षमता बढ़ जाएगी।

<u>बिहार</u>

बिहार राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे जोनों के अंतर्गत आती हैं। रेल परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

पिछले 3 वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2024-25) के दौरान बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले 3,889 किलोमीटर लंबाई के 72 सर्वेक्षण कार्य (12 नई लाइन और 60 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य में पूर्णत:/अंशतः पड़ने वाली 55 परियोजनाएं (31 नई लाइन, 02 आमान परिवर्तन और 22 दोहरीकरण) हैं, जिनकी कुल लंबाई 5,064 किलोमीटर तथा लागत ₹79,356 करोड़ है, जो योजना/अनुमोदन/निर्माण चरण में हैं, जिनमें से 1194 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर लिया गया है और मार्च, 2024 तक ₹26,983 करोड़ का व्यय किया गया है। इसका सार निम्नानुसार है :-

कोटि	परियोजनाओं की सं.	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)	परिव्यय 2024-25 (करोड़ रु. में)
नई लाइन	31	2712	464	13629	2516
आमान परिवर्तन	2	348	288	1520	60
दोहरीकरण/ मल्टीट्रैकिंग	22	2005	442	11834	2498
कुल	55	5064	1194	26983	5074

2014 से, परियोजनाओं के बजट आबंटन और उनकी तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना और अन्य संरक्षा कार्यों हेतु वार्षिक बजट आबंटन निम्नानुसार हैः-

वर्ष	परिव्यय	2013-14 के आबंटन की तुलना में वृद्धि
2013-14	₹1,245 करोड़	-
2023-24	₹8,505 करोड़	6 गुना से अधिक
2024-25	₹10,033 करोड़	8 गुना से अधिक

बिहार राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं की औसत वार्षिक कमीशनिंग निम्नानुसार है:-

वर्ष	कमीशनिंग	2009-14 के दौरान औसत वार्षिक कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	64 किलोमीटर प्रति वर्ष	-
2014-24	167 किलोमीटर प्रति वर्ष	2 गुना से अधिक

खगड़िया निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाली खगड़िया-कुशेश्वरस्थान (42 कि.मी.) नई रेल लाइन परियोजना एक स्वीकृत परियोजना है। कुल 42 कि.मी. लंबाई में से खगड़िया-अलौली (19 कि.मी.) खंड कमीशन कर दिया गया है और शेष अलौली-कुशेश्वरस्थान (23 कि.मी.) खंड में कार्य शुरू कर दिया गया है।

समस्तीपुर निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाली समस्तीपुर - दरभंगा (38 कि.मी.) दोहरीकरण परियोजना एक स्वीकृत परियोजना है। कुल 38 कि.मी. लंबाई में से, 26 कि.मी. खंड कमीशन कर दिया गया है और शेष खंड में कार्य शुरू कर दिया गया है।

रेल परियोजना/ओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना/ओं के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

*****